

संपादकीय

वर्षा त्रासदी से सबक

क्या होता है जब पाठकों और विद्वानों के लिए ये सुरक्षित ठिकाने मौत के जाल में बदल जाते हैं? 27 जुलाई को श्रेया यादव, निविन दलविन और तान्या सोनी, जो सभी बीस साल की उम्र के थे, दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर में बाढ़ से भरे बेसमेंट लाइब्रेरी में ढूब गए। तीनों यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) के उम्मीदवार राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल के छात्र थे, जो एक सिविल सेवा परीक्षा कोचिंग सेंटर है। संस्थान की लाइब्रेरी बिना किसी आधिकारिक मंजूरी के बेसमेंट में थी। दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार, संस्थान को अपने बेसमेंट का उपयोग केवल भंडारण, पार्किंग और उपयोगिता क्षेत्र के लिए करने की अनुमति थी उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, पड़ोस में भारी बारिश हुई जबकि शहर के कई अन्य हिस्से सूखे रहे। यह पहली बार नहीं था जब बारिश का पानी बेसमेंट लाइब्रेरी में भर गया था, लेकिन मूसलाधार बारिश के साथ-साथ कई स्तरों पर कुप्रबंधन और अवैधताओं ने इसे और भी भयंकर बना दिया। बाहर की सड़कें जलमग्न हो गईं। अतिक्रमण के कारण इलाके में बारिश के पानी की निकासी बाधित हो गई। रैप की वजह से बारिश का पानी नालियों में नहीं जा पा रहा था। दिल्ली नगर निगम के इंजीनियरों की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि जलभाराव वाले इलाके से गुजर रहे एक वाहन की वजह से इतनी लहरें उठीं कि संस्थान का एक गेट टूट गया, जिससे बारिश का पानी बेसमेंट लाइब्रेरी में भर गया। लाइब्रेरी में मौजूद करीब तीस छात्र बड़ी मुश्किल से बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन श्रेया, तान्या और निविन फंस गए। तीनों की मौत बारिश के पानी में ढूबकर हो गई। जांच जारी है। भारत की राजधानी में बाढ़ से भरे बेसमेंट लाइब्रेरी और ढूबकर हुई मौत को हम कैसे देखते हैं? मुझे बारिश से कभी डर नहीं लगा। यह रोमांस, कविता और संगीत का माहौल था। अब, जब भारी बारिश शुरू होती है, तो मुझे एक अजीब सा डर सताता है। भले ही मैं सीधे तौर पर प्रभावित न होऊँ, लेकिन मैं यह सोचना बंद नहीं कर सकता कि कोई, कहीं न कहीं बाढ़ से भरे बेसमेंट में फंसा हुआ है और अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। बचे हुए लोगों के अनुभव बताते हैं कि बंद जगह में पानी के भंवर में फंसे लोग किस तरह के डर और असहाय महसूस कर रहे हैं। अगर भारत की राजधानी में ऐसा हो सकता है, तो जरा छाटे शहरों की स्थिति की कल्पना करें? अपने जीवन के सबसे अच्छे दौर में तीन युवा भारतीयों की दुखद और पूरी तरह से रोकी जा सकने वाली मौतों ने कई चर्चाओं को जन्म दिया है। इनमें से एक मुख्य चर्चा शासन से संबंधित है। आश्चर्य की बात नहीं है कि अति-ध्रुवीकृत भारत में, यहां तक घटकि एक त्रासदी या आपदा भी एक भयंकर दोषारोपण के खेल को बढ़ावा देती है। आम आदमी पार्टी, जो वर्तमान में दिल्ली सरकार के साथ-साथ नागरिक निकाय (दिल्ली नगर निगम, एमसीडी) को नियंत्रित करती है और भारतीय जनता पार्टी, जो केंद्र में फैसले लेती है, दिल्ली पुलिस (केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत) को नियंत्रित करती है और जो अपने प्रतिद्वंद्वी और विपक्षी दल से सत्ता वापस छीनना चाहती है, के बीच एक मौखिक लडाई शुरू हो गई है। इससे कोई भी खुश नहीं होता। और नागरिकों के रूप में, हमें दोषारोपण के खेल को मूल मुद्दे से विचलित नहीं होने देना चाहिए — अवैधताओं की व्यापक स्वीकृति और सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन। राऊ का आईएएस स्टडी सर्किल किसी भी तरह से अलग नहीं था। मीडिया द्वारा की गई ग्राउंड रिपोर्ट एक भयावह तस्वीर पेश करती है। यह एक या दो या तीन नहीं है। दिल्ली भर में दर्जनों कोचिंग सेंटर बिल्डिंग कानूनों और सुरक्षा मानदंडों के घोर उल्लंघन के दोषी हैं। बेसमेंट में कई कलासरूम और लाइब्रेरी में आग या आपातकालीन निकास, बिजली भीटर नहीं थेय तार टूटे हुए थे और सीढ़ियाँ संकरी थीं। एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में हाल ही में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एक इलाके में नई इमारतों में भी छात्रों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए कदम उठाने के बजाय अवैध रूप से बेसमेंट में लाइब्रेरी और कलासरूम बनाए जा रहे हैं। यह सब विभिन्न सरकारी एजेंसियों की घोर लापरवाही या मिलीभगत की ओर इशारा करता है। एक छात्र ने पहले केंद्र, दिल्ली सरकार और एमसीडी को राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल द्वारा बेसमेंट के अवैध उपयोग और सुरक्षा मानदंडों की कमी के बारे में सचेत किया था। कुछ खास नहीं हुआ। यह भी आश्चर्य की बात है कि स्थानीय पुलिस सुरक्षा मानदंडों के घोर उल्लंघन से कैसे अनजान थी, जबकि कई संस्थान पुलिस स्टेशनों से पत्थर फेंकने की दूरी पर थे। लाइब्रेरी के अंदर ढूबने से मौत पहली बार हुई है, लेकिन इनमें से कई जगह आग लगने का खतरा भी था। पिछले साल, उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक यूपीएससी कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी। 61 छात्रों के साथ-साथ कुछ अन्य लोगों को हाथ, गर्दन और पैर जलने के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। हर जगह मौत के जाल हैं। और यह सिर्फ बाढ़ वाले बेसमेंट तक सीमित नहीं है। पुल ढह रहे हैं य फ्लाईओवर ढह रहे हैं और हवाईअड्डों पर छतरियां ढह रही हैं। इन सभी में एक बात समान है कि अवैधताएं, सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन और आम भारतीयों के जीवन और कल्याण के प्रति पूरी तरह से उपेक्षा। भारी बारिश को दोष देना आसान है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के समय में जो अनियमित और चरम मौसम को बढ़ावा देता है, दिल्ली जैसे अर्ध-शुष्क शहर में भी भारी बारिश होना आम बात हो गई है।

नहीं देते। यह बात दीगर है कि टैक्स और उसका संग्रह बढ़ता जाता है। यह बहस अनंत काल से चल रही है कि टैक्स मजबूरी है या जिम्मेदारी। सरकारें हमेशा से ऐसे जरूरत करती रही हैं कि अधिक से अधिक लोगों को टैक्स चुकाने पर राजी किया जाए। एक बार अमेरिका में तो राजस्व की कमी से परेशान सरकार ने एक कार्टून चरित्र को ही अपना टैक्स प्रचारक बना दिया। आइए, पकड़िए अपनी सीट टाइम मशीन में... हम उड़ चलते हैं अमेरिका की तरफ, जहां चुनाव की गहमागहमी बढ़ रही है। मगर हम कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप से मिलने नहीं जा रहे हैं। हम सीधे पहुंच रहे हैं 1930 के दशक में, जो अमेरिका का सबसे घटनाबहुल दशक था। इसी दौरान

डेमोक्रेट्स खुश, रिपब्लिकन असमंजस में

आदित्य
27 जून को जो बिडेन—डोनाल्ड प के बीच राष्ट्रपति पद की बहस कई घटनाक्रम हुए, जो अंततः 21 जूलाई को राष्ट्रपति जो बिडेन के हाथ से हटने के साथ समाप्त हुए। बीच पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हत्या का प्रयास हुआ। राष्ट्रपति बिडेन ने एक और कार्यकाल के ए अपनी शारीरिक और मानसिक टनेस के बारे में चिंताओं को दूर रहने के लिए मीडिया को संबोधित किया, लेकिन प्रत्येक उपस्थिति के अथ मामला बिगड़ता गया। बड़े नदाताओं और यहां तक छक्कि पूर्व उस स्पीकर नैन्सी पेलोसी और नीलीबुद्ध आइकन जॉर्ज क्लूनी ने भी इके बाहर निकलने की मांग में मिल होने के कारण दबाव बढ़ा। य की हत्या के असफल प्रयास ने नले को और बिगाड़ दिया क्योंकि ट्रम्प ने जनता की सहानुभूति त की और अपने वफादारों को साहित किया। यह अचानक हुआ केंकि श्री बिडेन, कोविड-19 के ए सकारात्मक परीक्षण के कारण बुद्ध तट पर अपने रिट्रीट तक मित थे, उन्होंने 21 जुलाई को अचाप एक पत्र जारी किया जिसमें होने अपने बाहर निकलने की मांग की। इसके तुरंत बाद, उन्होंने अपने पसंदीदा प्रतिरक्षण के रूप

में अपनी उपराष्ट्रपति कमला देवी हैंरिस का समर्थन किया। बदले में उन्होंने संभावित प्रतिद्वंद्वियों को बेअसर करने और 19–22 अगस्त को शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेशन में 3,636 प्रतिनिधियों में से अधिकांश का समर्थन हासिल करने के लिए बहुत तेजी से काम किया। सुश्री हैंरिस की ताकत और कमज़ोरियाँ दोनों हैं। सबसे पहले, आश्चर्य का तत्व राष्ट्रपति बिडेन को संभालने के लिए तैयार ट्रम्प अभियान को पकड़ लेता है। अब उन्हें जल्दी से फिर से संगठित होना चाहिए और हमले की एक नई लाइन तैयार करनी चाहिए। दूसरा, क्योंकि वह एक अति-सक्रिय उपराष्ट्रपति नहीं थीं, इसलिए वह बिडेन प्रेसीडेंसी के अलोकप्रिय नीतिगत निर्णयों से अलग हो सकती हैं। तीसरा, श्री ट्रम्प से दो दशक छोटी होने के कारण, उम्र का तर्क, जो श्री बिडेन के लिए बोझ था, अब श्री ट्रम्प के गले में लटक रहा है। नकारात्मक पक्ष यह है कि वह कैलिफोर्निया से आती हैं, और इस प्रकार उन्हें आसानी से उदारवादी करार दिया जा सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें एक बड़े और शक्तिशाली राजनेता विली ब्राउन के साथ डेटिंग करके राजनीतिक संरक्षण मिला, हालांकि वह अपनी पत्नी से अलग हो चुके थे। इसके अलावा, उन्हें उसी लैंगिक पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ रहा है जिसका सामना हिलेरी किलंटन ने 2016 में किया था। 2020 के राष्ट्रपति पद के प्राइमरी के दौरान उन्हें सैन फ्रांसिस्को (2004–11) के जिला अटॉर्नी और कैलिफोर्निया (2011–17) के अटॉर्नी—जनरल के रूप में अप्रीकी—अमेरिकी अपराधियों पर कानून के अत्यधिक सख्त प्रवर्तक के रूप में भी लेबल किया गया था। नीतिगत मुद्दों पर, महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के उनके मजबूत बचाव से उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का समर्थन हासिल करने में मदद मिलेगी। यह श्री ट्रम्प के साथी जे.डी. वेंस के रुख के विपरीत है। सुश्री हैंरिस भी गाजा युद्ध पर इजरायल को बिडेन प्रशासन के लगभग बिना शर्त समर्थन से खुद को जल्दी से दूर करने में सक्षम रही हैं। जैसे—जैसे नागरिक हताहत होते गए, अमेरिका में, विशेष रूप से प्रमुख विश्वविद्यालय परिसरों में जनता की राय टूटती गई। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को इजरायल के प्रधान मंत्री बैंजामिन नेतन्याहू के संबोधन को छोड़कर असहजता का संकेत दिया। वह उनसे अलग से मिलीं और जाहिर तौर पर इजरायली अभियानों पर अपनी नाखुशी व्यक्त

की। रिपब्लिकन और विशेष रूप से डोनाल्ड ट्रम्प के लिए रोटी और नक्खन का मुहा आव्रजन है। वे उन्हें अप्रवास का घ्यारां कहते हैं, जबकि उनकी भूमिका समस्या के



मूल कारणों की खोज तक सीमित थी। वे 2021 में उपराष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली विदेश यात्रा पर ग्वाटेमाला गई, ताकि यह अधियन किया जा सके कि किस तरह से प्रवास को स्रोत पर ही रोका जा सकता है। डेमोक्रेटिक जवाब यह थे कि यह डोनाल्ड ट्रम्प ही थे जेन्होंने कांग्रेस में इस विषय पर द्वेदलीय समझौते को रोका था। बेडेन प्रशासन ने सीमा की दीवार के निर्माण को धीमा कर दिया और अधिकारों को माता-पिता से अलग करने की भायानक प्रथा को रोक दिया। लेकिन दीवारें लोगों की आवाजाही को नहीं रोकती हैं। इसका



A portrait of Kamala Harris, Vice President of the United States, speaking at a podium with microphones. She is wearing a dark blue blazer over a white collared shirt and a necklace. The background is blurred, showing what appears to be a press conference or public event.

वेंस की पत्नी तेलुगु हैं, कुछ लोगों
ने इसे आंध्र प्रदेश बनाम तमिलनाडु
की प्रतियोगिता कहा। हल्केपन को
छोड़ दें, तो भारतीय मूल का कोई
भी व्यक्ति, और उससे भी कम मिश्रित
नस्ल का, जो संयुक्त राज्य अमेरिका
में पैदा हुआ और पला-बढ़ा है,
सबसे पहले अमेरिकी हितों के बारे
में सोचेगा। संयुक्त राष्ट्र में हमारे
स्थायी प्रतिनिधियों को, जब निकटी
हेली अमेरिकी राजदूत थीं, आदि
एकारिक तौर पर उनसे कोई विशेष
व्यवहार नहीं मिला। हालांकि,
सामाजिक स्तर पर, उनसे जुड़ना
आसान था। हालांकि, सुश्री हैरिस

मंत्रालय के मुताबिक खेजगारी तेजी से घटी

पा. चंद्रबरम
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
23 जुलाई व को साल 2024-25
बजट पेश किया। उसके आगले
न संसद के दोनों सदनों में इस
चर्चा शुरू हुई, जबकि वित्त
मंत्री ने लोकसभा में 30 जुलाई
र राज्य सभा में 31 जुलाई को
उका जवाब दिया। वित्त मंत्री का
जवाब तीन बड़े आधारों पर टिका
...
सातवाहन वास्तव में अधिक ऐसा

सरकार हर मद में आधिक पसार्व कर रही है। वित्त मंत्री के अनुसार, पैसे वर्च करना अच्छी शासन व्यवस्था एक मापदंड है। इसके नस्वरूप हर वर्ग के लोगों का काफ़ास और कल्याण होता है। वित्त मंत्री ने अपनी बात को आंकड़ों के रिये पुष्ट करने का प्रयास किया। हमने कहा कि यूपीए सरकार ने अपने शासन के अंतिम साल 2013-14 में कितना खर्च किया था और एनडीए सरकार के ले और आखिरी साल यानी 2019-20 में कितना खर्च किया था और 2024-25 में कितना

8

खर्च किया जाएगा। जाहार तार पर संख्या यह दर्शाती है कि साल दर साल बजट में इजाफा हुआ है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 2013–14 में कृषि के लिए मात्र 30 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जबकि आज यह 1.52 लाख करोड़ रुपये है। यहां तक कि यह पिछले साल 2023–24 से भी आठ हजार करोड़ रुपये अधिक है। पिछले साल की तुलना में हमने इसमें वृद्धि की है, न कि कोई कमी। परेशानी मौजूदा कीमतों को लेकर थी, न कि स्थिर कीमतों को लेकर। बढ़ा हुआ व्यय उसी सूरत में प्रासंगिक होगा, जब इसे कुल व्यय या सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के अनुपात में बताया जाएगा। इसके अलावा ऐसे अनेक मद हैं, जिनके लिए आवंटित राशि को 2023–24 में खर्च ही नहीं किया गया। इसके बारे में नहीं बताया गया, क्यों?

2. बेरोजगारी की समस्या है ही नहीं

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की नीति लोगों को सक्षम, स्वतंत्र

र समथ बनान का ह। उन्हाना धिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़े ते हुए कहा कि बेरोजगारी में प्रतिशत की गिरावट आई है। बीआई की शोध रिपोर्ट में पाया कि 2014 से लेकर 2023 ते 125 मिलियन रोजगार पैदा गए। ये दोनों सरकारी रिपोर्ट सीएमआईई ने सरकार की रिपोर्ट का खंडन करते हुए कि मौजूदा बेरोजगारी दर 9. प्रतिशत है। अंतरराष्ट्रीय श्रम ठन की रिपोर्ट के अनुसार, त में जितनी बेरोजगारी है, में 83 प्रतिशत युवा हैं। वित्त ने इस सवाल का जवाब नहीं पा कि सैकड़ों या हजारों नरियों के लिए लाखों उम्मीदवार हैं? उदाहरण के लिए यूपी नस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 244 पदों के लिए 48 लाख से बढ़ा उम्मीदवारों ने परीक्षा दी, नमें 16 लाख महिलाएं थीं। र बेरोजगारी तेजी से घट रही तो नौकरी में पदों और नीदवारों का अनुपात इतना मान क्यों है? ऊपर के दो

उदाहरण में पद आर आवेदकों का अनुपात 1:80 और 1:329 था। इंजीनियर, मैनेजमेंट ग्रेजुएट, वकील और पीजी किए हुए छात्र एक कांस्टेबल या कर्लर्क के पद के लिए क्यों आवेदन कर रहे हैं? विवेरोजगारी की सच्चाई को जानने के लिए मैं प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को यह सुझाव देना चाहता हूँ कि उन्हें भारत के शहरों और ग्राम्य क्षेत्रों की गलियों में घूमना चाहिए। वित्त मंत्री तो अपने जन्म स्थान नदुरई से अपनी यात्रा शुरू कर वेल्लुपुरम, जहां उन्होंने स्कूल की पढ़ाई की, जा सकती हैं और तेलुचियापल्ली, जहां उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की है, मैं अपनी यात्रा समाप्त कर सकती हूँ।

3. हमारी मुद्रास्फीति दर आपसे बेहतर है!

वित्त मंत्री ने कहा, व्यूपीए सरकार दार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से पढ़े नेताओं द्वारा चलाई जा रही थी। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि प्रोत्साहन को कब और कैसे हटाना है, जिसकी प्रजह से 2009 से 2013 के बीच मुद्रास्फीति दोहरे अकों तक पहुँच

गई। बड़ा हा चालाका स उन्हाने किसी का नाम न लेते हुए अपनी सरकार को फजीहत से बचा लिया। वित्त मंत्री तकनीकी रूप से सही थीं, पर मुझे लगता है कि उनका वक्तव्य प्रांसंगिक नहीं है। लोग अब यूपीएयुग में नहीं, बल्कि मोदी 2.1 के समय में रह रहे हैं।

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार, वे ऐसे समय में रह रहे हैं, जहां टमाटर, प्याज और आलू के दाम साल दर साल 30, 46 और 59 प्रतिशत की दर से बढ़े हैं। वे ऐसे समय में रह रहे हैं, जब थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 3.4 प्रतिशत है यी सीपीआई मुद्रास्फीति 5.1 प्रतिशत है और खाद्य मुद्रास्फीति 9.4 प्रतिशत है। वे एक ऐसे समय में जी रहे हैं, जब सभी श्रेणियों की मजदूरी पिछले छह सालों में स्थिर हो गई है। जब लोगों ने अप्रैल-मई 2024 में वोट दिया था तो उन्होंने यूपीएसरकार के समय में रही मुद्रास्फीति के खिलाफ नहीं, बल्कि मोदी सरकार के काल की मुद्रास्फीति के खिलाफ वोट दिया था।

वित्त मंत्री ने ऐसा कोई विचार नहा सुझाया, जिसस मुद्रास्फीति को कम किया जा सके। उन्होंने न तो कीमतों में कोई कमी की, न ही करों या उपकरों में, न न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई और न ही आपूर्ति बढ़ाने के लिए कोई प्रोत्साहन दिए। उन्होंने मुद्रास्फीति पर मुख्य आर्थिक सलाहकार के 15 शब्दों का उदाहरण दिया, भारत की मुद्रास्फीति लगातार कम, स्थिर और चार प्रतिशत के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, इतना कहकर विषय को खारिज कर दिया। वित्त मंत्री ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि अगर मुद्रास्फीति प्रबंधन इतना प्रशंसनीय था तो रिजर्व बैंक ने पिछले 13 महीनों से बैंक दर को 6.5 प्रतिशत क्यों कर रखा है? और इस साल इसमें कोई कमी भी नहीं होने वाली है। बजट पर आम लोगों की प्रतिक्रिया भी उतनी अच्छी नहीं रही। यहां तक कि सरकार की बढ़ाई करने वाले भी डरे और सशंकित थे। अंत में वित्त मंत्री के जवाब से अन्य लोगों की तरह मैं भी उसी तरह की स्थिति में था, जैसा कि हम उनके बजट पेश करने के समय थे।

शक्ति के विकास का नुकसान

आप

न मनाया जाना चाहिए। भले ही द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार दोहराना न भूले कि इस काले र के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है उसने 25 जून को संविधान दिवस भी घोषित किया है, केन केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने शिक्षा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती वी में डालने के 1976 के फैसले

से चली आ रही व्यवस्था ने संघवाद को कायम रखा। व्यावहारिक स्तर पर इसने राज्यों को क्षेत्रीय, जातीय और भाषाई रूप से विविधतापूर्ण देश में युवाओं को उनकी जरूरतों के हिसाब से शिक्षित करने के लिए अपना रास्ता बनाने की अनुमति दी। शिक्षा को समर्पित सूची में डालने का मतलब था राज्यों और केंद्र के बीच सहयोग, जो एक अच्छी

नक्षेप राज्यों की समझ और हार के साथ संतुलित हो। लेकिन र केंद्र की सरकार एक ही अस्था बनाने के नाम पर विचार, ते और पद्धति की पूरी जगह पने की कोशिश करती है, तो मति का बिंदु विफल हो जाएगा। राज्यों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। इस असंतुलन का कुछ रा पहले से ही देखा जा सकता

हैं। हाल ही में, अखिल भारतीय स्तर पर प्रवेश और योग्यता परीक्षा आयोजित करने के लिए श्री मोदी की सरकार के तहत गठित राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, राष्ट्रीय प्रवेश-सह-पात्रता परीक्षा में लीक हुए पेपर और ब्रष्ट अंकन के आरोपों प्रौढ़ और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के आयोजन के एक दिन बाद ही इसे दृष्ट करने के साथ गंभीर रूप से

पहले से ही थींय वे इस साल चरम पर पहुँच गईं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेस टेस्ट ने अपनी शुरुआत से ही संस्थानों से उनकी जरूरतों और फोकस क्षेत्रों के अनुसार अपने स्वयं के प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के अधिकार को छीनकर असंतोष पैदा किया। शिक्षा में एक ही आकार सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। देश के लिए अनुकूलता का शिक्षा मंत्री

जब विभिन्न संस्थानों के अलग-अलग लक्ष्य होते हैं और वे अलग-अलग विषयों के संयोजन में अलग-अलग क्षमताओं और आकांक्षाओं वाले छात्रों को प्रशिक्षित करते हैं। इसके अलावा, यह विचार कि किसी विषय के बारे में छात्र की समझ और योग्यता को मापने के लिए केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पर्याप्त हैं, मूर्खता की पराकाढ़ा है।

सरकारें टैक्स लगाए बिना चल नहीं सकती

रुजवेल्ट और मोर्गनथाउ के बीच गाढ़ी दोस्ती के किस्से खूब सुने जा रहे हैं। यह साल 1934 है। रुजवेल्ट राष्ट्रपति हैं और मोर्गनथाउ उनके वित्त मंत्री। मोर्गनथाउ रुजवेल्ट के मंदी निवारण अभियान के वित्तीय मैनेजर थे। अमेरिका को गहरी मंदी से उबारने के लिए संसाधनों का जुगाड़ मोर्गनथाउ ने ही किया है। आपको पता तो चल ही गया होगा कि दूसरे विश्वयुद्ध की तोरें गरजने लगी हैं। हिटलर के यहूदी संहार के खिलाफ अमेरिका की सबसे बड़ी आवाज बनकर गरज रहे हैं हेनरी मोर्गनथाउ। उनके कहने पर अमेरिकी सरकार ने बार रिफ्यूजी बोर्ड बनाया है, जिससे जनसंहार के शिकार यहूदियों को मदद दी जा रही है। इस बीच पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला कर दिया है। यारे विवाह से जल जल जा

अमेरिका अब इस लड़ाई में कूदने गा है। मगर हम यहां से उड़ते हैं कैलिफोर्निया, व्योमिंग टैक्स जिस कहानी को तलाशते हुए करीब 80 साल पीछे आए हैं, के लिए मनोरंजन के नायक वाल्ट ल्नी से मिलना होगा। हां, वही वाल्ड डक, मिकी माउस और इन असंख्य चरित्र देने वाले प्रसिद्ध रून महानायक वाल्ट डिज्नी। अमेरिका विश्वयुद्ध में शामिल होने के दृष्टियार बांध रहा है। वित्त मंत्री नंथाउ को युद्ध के लिए संसाधन हैं। अमेरिका में वार बॉन्ड जारी दिए गए हैं। मोर्गनथाउ को लगता के अगर अमेरिकी लोगों को समय टैक्स चुकाने के लिए प्रेरित किया गया, तो संसाधनों की किल्लत दूर जाएगी। यह दिसंबर, 1941 है।

फैलिफोर्निया आ गए हैं, जहां वाल्ट डेज्जी मोर्गनथाउ का संदेश पढ़ रहे हैं। बरबैंक से पहली उड़ान पकड़ डेज्जी वाशिंगटन डीसी पहुंच रहे हैं। डेज्जी को लगा था कि उन्हें युद्ध बॉन्ड के प्रचार में मदद करनी होगी, नगर मोर्गनथाउ का एजेंडा दूसरा था। मोर्गनथाउ ने डिज्जी स्टूडियो को रेसी फिल्म बनाने के लिए कहा है, जो लोगों को वक्त पर टैक्स चुकाने के लिए प्रेरित करे। केवल छह सप्ताह का समय दिया गया है। यह फिल्म नरवरी, 1942 तक सिनेमाघरों में रेलीज की जाएगी। डिज्जी स्टूडियो में बनती सभी फिल्में रोक कर एक शॉर्ट फिल्म पर काम शुरू हो गया है। डोनाल्ड डक सबसे बड़ा कार्टून स्टार है, जो इस फिल्म का नायक होगा। जो ग्रांट और विल हूमर ने

स्पिरिट। स्टोरीबोर्ड लेकर वाल्ट डिज्जी फिर वाशिंगटन लौट आए हैं। बैठक लगी है। मगर यह क्या? मोर्गनथाउड डोनाल्ड डक के प्रशंसक नहीं हैं, उन्हें फ़िल्म का मजमून पसंद नहीं आया। कार्टूनों के निर्माता डिज्जी वित्त मंत्री मोर्गनथाउड से नाराज हैं। हों भी क्यों न? डोनाल्ड डक, डिज्जी स्टूडियो का मेगास्टार है। उसके नाम पर फ़िल्में दौड़ती हैं। यह फ़िल्म सिनेमावरों को मुफ्त दी जानी है, जिसके कारण डिज्जी स्टूडियो की अन्य फ़िल्मों की बुकिंग कैंसिल हो रही है। डिज्जी की कंपनी को 40,000 डॉलर का नुकसान होने जा रहा है। इधर 10 लाख डॉलर का कर्ज बैलेंस शीट में खड़ा है। डिज्जी स्टूडियो वहुत कुछ कुर्बान कर रहा है, मगर मोर्गनथाउड को लिए आवाज़ में भी चर्चा आ रही है।

पर वक्त डिज्जी के साथ है, मोर्गनथाउड के साथ नहीं। सरकार के पास वक्त कम है। अमेरिका में आयकर रिटर्न भरने की तारीख 15 मार्च तक है। इसलिए द न्यू स्पिरिट को मंजूरी मिल ही गई। अब हम न्यूयॉर्क के सिनेमाघर के सामने हैं। यहां पहली बार द न्यू स्पिरिट दिखाई जा रही है। फ़िल्म छा गई है। इस फ़िल्म में डोनाल्ड डक एक अभिनेता है। उसे टैक्स चुकाने का राष्ट्रीय कर्तव्य समझ में आता है, तो वह उत्साह में अपना रिटर्न लेकर सीधे वाशिंगटन पहुंच जाता है। इस फ़िल्म का डायलॉग मशहूर होने लगा है—टैक्सेस दू बीट द एक्सिस। अर्थात हिटलर—मुसोलिनी के गठजोड़ (एक्सिस) को हराने के लिए टैक्स लड़ाया जाएगी है।

